are covered by the Gazette Notification of 7.9.2015 or any of them is included as foreigners among the 988?

MR. CHAIRMAN: If you don't have the information, collect the information with confirmation, and then pass on the information. आपके पास अभी जानकारी नहीं है, तो आप बाद में कलेक्ट करके भिजवा दीजिएगा।

श्री नित्यानन्द राय: सभापति जी, यह बात सही है कि 988 लोगों को नजरबंद रखा गया है। हमारे यहाँ जो ग़ैर-कानूनी ढंग से रह रहे हैं, उनमें वे लोग हैं, जो या तो पासपोर्ट लेकर आए हैं या जो जरूरत के कागजात लेकर आए हैं, उनकी समय-सीमा समाप्त होने के बाद रह रहे हैं या फिर ऐसे लोग, जो बिना किसी कागजात के, बिना किसी पासपोर्ट के आ जाते हैं उनको भी हम ग़ैर-कानूनी ढंग से रहने वाले लोगों में मानते हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति: उन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। यदि आपके पास उसका जवाब है, तो दीजिए, अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भिजवा दीजिए, क्योंकि it is a sensitive matter.

श्री नित्यानन्द राय: आप जितना विस्तृत जवाब चाहते हैं, उसमें वह है, लेकिन यदि आप इस पर और ज्यादा जवाब चाहते हैं, तो हम उसका जवाब आपको लिखकर दे देंगे।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन और मांग

*104. **सुश्री सरोज पाण्डेय:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में प्रतिवर्ष प्राकृतिक गैस का कुल उत्पादन कितना है और घरेलू मांग को देखते हुए क्या यह पर्याप्त है;

(ख) इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए और प्राकृतिक गैस के नए भण्डारों को खोलने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं; और

(ग) वर्ष 2022 तक देश में प्रति वर्ष प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष अप्रैल-सितम्बर, 2019 के लिए प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन और खपत (बीसीएम में) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	2018-19	2019-20 (अप्रैल-सितम्बर, 2019)
प्राकृतिक गैस का उत्पादन	32.87	16.01
प्राकृतिक गैस की खपत	60.75	31.82

* बीसीएम - बिलियन घन मीटर।

(ख) देश में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सुधारात्मक नीतिगत उपाय/पहलें की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) हाइड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत रियायतों, अवधि बढ़ाए जाने और स्पकष्टीकरणों के लिए नीति, 2014

(ii) खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015

(iii) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, 2016

(iv) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की अवधि बढ़ाने के लिए नीति, 2016 और 2017

(v) कोल बैड मिथेन से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए नीति, 2017

(vi) नेशनल डाटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017

(vii) तलछटीय बेसिनों में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन

(viii) हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन: आकलन

(ix) एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्लॉकों में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए नीतिगत ढांचा, 2018

(x) तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए नीति, 2018

(xi) मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं, कोल बेड मिथेन संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन हेतु नीतिगत ढांचा, 2018

(xii) उच्च दाब-उच्च तापक्रम (एचपी-एचटी) रिज़र्वायर्स तथा गहरे समुद्री और अत्यधिक

गहरे समुद्री क्षेत्रों (सीमा सहित) से प्राकृतिक गैस के उत्पादन, सीबीएम ब्लॉकों से उत्पादित गैस, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) तथा खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति के अंतर्गत दिए गए ब्लॉक दिनांक 01 जुलाई, 2018 तक अथवा उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) से उत्पादित वाणिज्यिक गैस तथा ऐसी नई गैस खोजों के संबंध में मूल्य निर्धारण की आज़ादी के साथ-साथ विपणन का अधिकार देना, जिनकी क्षेत्र विकास योजना का अनुमोदन फरवरी, 2019 के बाद हुआ है। प्रशासित मूल्य तंत्र व्यवस्था (एपीएम) क्षेत्रों से अतिरिक्त गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सामान्य कारोबारी परिदृश्य से अतिरिक्त उत्पादन किए जाने पर लागू रॉयल्टी के 10% तक रॉयल्टी में कटौती करने की भी मंजूरी दी गई है।

(xiii) इसके अलावा, सरकार ने अन्वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, तलछटीय बेसिनों के गैर-अन्वेषित/गैर-आबंटित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी, 2019 में अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित कर दिया है। नीतिगत सुधारों के लक्ष्य में अन्य बातों के साथ-साथ कार्य कार्यक्रम को और ज्यादा प्राथमिकता देते हुए अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, सरकार के साथ बगैर किसी उत्पादन अथवा राजस्व हिस्सेदारी के श्रेणी II और III के तलछटीय बेसिनों के संबंध में अन्वेषण ब्लॉकों की बोली लगाना शामिल है। इसके अलावा, किए जाने वाले सुधारों में राजकोषीय और संविदागत शर्तों को सरल बनाना, राजकोषीय प्रोत्साहन दे कर खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करना, विपणन और मूल्य निर्धारण की आज़ादी देते हुए गैस उत्पादन बढ़ाना, नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की पद्धतियों हेतु सहयोग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को काम करने की और ज्यादा आज़ादी देना, अनुमोदन की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना तथा इलैक्ट्रॉनिक एकल खिड़की व्यवस्था के साथ आसानी से कारोबार बढ़ाना भी नीतिगत सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

(ग) वर्ष 2022 तक प्राकृतिक गैस का अनुमानित घरेलू उत्पाोदन निम्नवत है:-

वर्ष	प्राकृतिक गैस (बीसीएम में)
2019-20	34.55
2020-21	39.32
2021-22	46.92

* बीसीएम - बिलियन घन मीटर

Production and demand of natural gas

†*104. MS. SAROJ PANDEY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the total production of natural gas per annum in the country at present and whether this is sufficient in view of the domestic demand;

(b) the steps taken by Government to increase this production and to open new natural gas reserves; and

(c) the estimated increase in production of natural gas per year till 2022 in the country?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the Home.

Statement

(a) Domestic production and consumption of natural gas (in BCM) for the year 2018-19 and for current year from April-September, 2019 is as under:–

	2018-19	2019-20 (April - Sept., 2019)
Production of Natural Gas	32.87	16.01
Consumption of Natural Gas	60.75	31.82

*BCM- Billion Cubic Metre.

(b) Government has taken several transformative policy measures/initiatives to enhance exploration and production of oil and gas in the country, which include:

(i) Policy for Relaxations, Extensions and Clarifications under Production Sharing Contract (PSC) regime for early monetisation of hydrocarbon discoveries, 2014.

(ii) Discovered Small Field Policy, 2015.

(iii) Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy, 2016.

(iv) Policy for Extension of Production Sharing Contracts, 2016 and 2017.

†Original notice of the question was received in Hindi.

(v) Policy for early monetisation of Coal Bed Methane, 2017.

(vi) Setting up of National Data Repository, 2017.

(vii) Appraisal of Unappraised areas in Sedimentary Basins.

(viii) Re-assessment of Hydrocarbon Resources.

(ix) Policy framework to streamline the working of Production Sharing Contracts in Pre-NELP and NELP Blocks, 2018.

(x) Policy to Promote and Incentivise Enhanced Recovery Methods for Oil and Gas, 2018.

(xi) Policy framework for exploration and exploitation of Unconventional Hydrocarbons under existing Production Sharing Contracts, Coal Bed Methane contracts and Nomination fields, 2018.

(xii) Grant of Marketing including pricing freedom, on natural gas production from High Pressure - High Temperature (HP-HT) reservoirs and deepwater and ultra deepwater areas (with ceiling), gas produced from CBM blocks, blocks awarded under Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP) and Discovered Small Fields (DSF) Policy, commercial gas produced from North-Eastern Region (NER) on or after 1st July, 2018 and also in those new gas discoveries whose Field Development Plan (FDP) has been approved after February, 2019. To incentivise additional gas production from Administered Price Mechanism (APM) fields, reduction in royalty by 10% of the applicable royalty has also been granted on the additional production over and above business-as-usual scenario.

(xiii) In addition, Government in February, 2019 approved major reforms in exploration and licensing policy to enhance exploration activities, attract domestic and foreign investment in unexplored/unallocated areas of sedimentary basins and accelerate domestic production of oil and gas from existing fields. The policy reforms *inter alia* aim to boost exploration activities with greater weightage to work programme and bidding of exploration blocks under Category II and III sedimentary basins without

any production or revenue sharing to Government. Further, reforms envisage simplified fiscal and contractual terms, early monetisation of discoveries by extending fiscal incentives and incentivising gas production including marketing and pricing freedom. The policy also provides more functional freedom to National Oil Companies for collaboration and private sector participation for production enhancement methods in nomination fields. Streamlining approval processes and promoting ease of doing business including electronic single window mechanism is also an important aspect of policy reforms.

(c) Projection of domestic natural gas production till 2022 is as below:–

Year	Natural Gas (in BCM)
2019-20	34.55
2020-21	39.32
2021-22	46.92

*BCM- Billion Cubic Metre.

सुश्री सरोज पाण्डेय: सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को बधाई देती हूं कि उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय में बहुत सारे विषयों पर बहुत बेहतरी से काम किया है और ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण का विषय मजबूत हुआ है। जो जानकारी दी गई है, उसमें तेल और गैस ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप क्वेश्चन पूछिए।

सुश्री सरोज पाण्डेय: सभापति जी, मैं क्वेश्चन पर ही आ रही हूं कि उसमें तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए जो जानकारियाँ दी गई हैं, क्या उनके क्रियान्वयन की शुरुआत हो चुकी है?

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सर, इसके लिए कई प्रकार के उपाय शुरू किए गए हैं। देश में गैस कैसे बढ़े, आदरणीया सदस्या ने यह पूछा था, हमने लिखित रूप में उसका विस्तृत विवरण दिया है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 105. The questioner is not present.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Status of the projects under Smart Cities Mission

105. DR. PRABHAKAR KORE: Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, a recent report brought out by the 'Smart Cities Council India' on the project across the country claims that the projects are progressing at a very good pace;

(b) if so, the status of the projects under the Smart Cities Mission, State-wise; and

(c) the detailed status of all the works of Belagavi Smart City Project in Karnataka;

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): (a) to (c) Yes, Sir. Government of India launched the Smart Cities Mission (SCM) on 25th June, 2015 for development of 100 cities as Smart Cities. The selection of 100 Smart Cities has been completed through 4 rounds of selection from January, 2016 to June, 2018. A total of 5,151 projects worth of ₹ 2,05,018 crore have been proposed by the 100 Smart Cities as part of their Smart City Proposals (SCPs) that are under various stages of implementation.

As per Smart Cities Mission Statement and Guidelines, the Central Government proposes to give financial support to the extent of ₹ 48,000 crore over five years *i.e.* an average of ₹ 500 crore per city over the Mission period. An equal amount on a matching basis, is to be provided by the State/Urban Local Bodies. Apart from these, around ₹ 42,028 crore (21%) is expected from convergence with other Missions, ₹ 41,022 crore (21%) from PPP, around ₹ 9,843 crore (4.8%) from loans, ₹ 2,644 crore (1.3%) from own resources and remaining from other sources.

As on 18th November 2019, 4,178 projects worth ₹ 1,49,512 crore have been tendered out, which is about 73 per cent of the total value of projects. Out of these, the work orders have been issued for 3,376 projects worth ₹ 1,05,458 crore and 1,296 projects worth ₹ 23,170 crore have been completed. Since, the last 15 months, there has been 183% growth in projects tendered, 224% growth in projects grounded/ completed and 284% growth in projects completed. State-wise/City-wise progress of projects is given in Statement (*See* below).

As regards Belagavi Smart City, it was selected in January 2016 in the Round-1 of the Smart Cities Challenge. The present status of projects in Belagavi Smart City is given below:-